क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 143, रविवार, 17 जून 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

सिपाही भर्ती 60 हजार रुपए में पेपर आउट कराने की कोशिश, शिक्षक और कोचिंग प्रबंधक गिरफ्तार

आजमगढ़ (एजेंसी)। आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान स्थित विश्वा कोचिंग सेंटर पर शनिवार को पुलिस ने छापा मार कर पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट करने से पहले रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया। कोचिंग प्रबंधक सहित शिक्षक को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तीन मोबाइल, छात्रों की मार्कशीट, आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार प्रबंधक ने छात्रों से साल्वड पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर 60-60 हजार रुपये का सौदा किया था। मुखबिर व सर्विलांस के माध्यम से सूचना मिली कि शहर के ब्रह्मस्थान स्थित विश्वा कोचिंग सेंटर के कुछ छात्रों से प्रबंधक द्वारा पुलिस की लिखित परीक्षा में साल्वड पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। इस पर शनिवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के नोडल प्रभारी/एसपी सिटी सुभाषचंद गंगवार, सीओ नगर सच्चिदानंद के निर्देश पर नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को सादे वर्दी में कोचिंग सेंटर के आस-पास लगाया गया था। इस दौरान कुछ छात्रों को कोतवाली में लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि कोचिंग में लिखित परीक्षा संबंधी साल्वड पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर 60-60 हजार रुपये की मांग की गई है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कोचिंग पर छापेमारी कर प्रबंधक सहित एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी सुभाषचंद गंगवार ने बताया कि गिरफ्तार कोचिंग प्रबंधक शिवचरन विश्वकर्मा पुत्र विंध्याचल विश्वकर्मा अहरौला थाने के संभूपुर गांव का निवासी है। जबकि कोचिंग का शिक्षक रविकांत पांडेय पुत्र रामाज्ञा पांडेय कप्तानगंज थाने के भवनपुर गांव का निवासी है। दोनों के पास से तीन मोबाइल, पांच हजार छह सौ रुपये ,हाई स्कूल,इंटर की 12 अंकपत्र, दो आधार कार्ड बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार प्रबंधक,शिक्षक की ओर से फर्जी तरीके से पुलिस आरक्षी परीक्षा का साल्वड पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर कोचिंग के छात्रों से धन उगाही की जा रही थी।

राइफलमैन औरंगजेब की हत्या से पहले आतंकियों ने लिया था मेजर शुक्ला का नाम, जानें कौन हैं ये मेजर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर के बाद मेजर रोहित शुक्ला का नाम खूब चर्चा में रहा। इस एनकाउंटर के दौरान उन्होंने हिजबुल के आतंकी को ढेर किया था। मेजर शुक्ला को समीर टाइगर ने चैलेंज किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना में राइफलमैन औरंगजेब जब ईद मनाने के लिए घर आ रहे थे तब गुरुवार की सुबह आतंकियों ने पुलवामा के कलामपोरा में उन्हें अगवा कर लिया। बाद में उनकी लाश कलामपोरा से 10 किलोमीटर दूर गुसु गांव में मिली थी। उनके सिर और गले में गोली मारी गई थी। औरंगजेब की हत्या से पहले आतंकियों ने उनका वीडियो शूट किया और उनसे कुछ सवाल पूछे। पूछताछ के दौरान आतंकियों ने मेजर रोहित शुक्ला का नाम लिया। अब सवाल ये उठता है कि मेजर शुक्ला हैं कौन?

पुलवामा एनकाउंटर से चर्चा में आए मेजर रोहित शुक्ला

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर के बाद मेजर रोहित शुक्ला का नाम खूब चर्चा में रहा। इस एनकाउंटर के दौरान उन्होंने हिजबुल के आतंकी को ढेर किया था। मेजर शुक्ला को समीर टाइगर ने चैलेंज किया था और उन्होंने अगले ही दिन समीर टाइगर को ढेर कर दिया। 44 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के मेजर रोहित शुक्ला इस एनकाउंटर में घायल हो गए थे। जिसके बाद उन्हें श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था। सर्जरी के बाद अब वह ठीक हैं।

शौर्य चक्र से हो चुके हैं सम्मानित

मेजर रोहित शुक्ला ने द्रब्गाम में हिजबुल कमांडर समीर टाइगर व उसके साथी आकिब खान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। मेजर को इससे पूर्व भी सफल ऑपरेशन के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है।

माता-पिता को मेजर पर गर्व

मेजर रोहित के माता-पिता को उनकी इस बहादुरी पर गर्व है और वह अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनके माता-पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। मेजर रोहित देहरादून के रहने वाले हैं।

त्रिपुरा, मणिपुर में बाढ़ से राहत और बचाव के लिए सेना को तैनात किया गया है। शुक्रवार को सेना ने 1380 लोगों को रेस्क्यू और 2000 हजार लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया।

वाराणसी :मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद गई 6 मरीजों की आंखों की रोशनी

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के मारवाड़ी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद छह मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि, मामले की जांच में जुटे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वी. बी. सिंह ने शनिवार को बताया कि सभी मरीजों का इलाज चल रहा है तथा उनकी रोशनी लौटने की संभावना है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अख्तरी बेगम, मालती देवी, पार्वती देवी, वंदना, त्रिवेणी और यज्ञ नाराणसी सिंह का गत 12 जून को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि चौबीस घंटे बाद जब आंखों की पट्टी खोली गई तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने उन्हें फिर बताया कि अगले 72 घंटे में रोशनी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मरीजों के तीमारदारों ने शक्रवार देर शाम हंगामा किया और इसकी शिकायत पुलिस से की।

उन्होंने बताया कि अख्तरी बेगम वाराणसी के नवाबगंज और मालती देवी कोनिया की निवासी हैं, जबकि त्रिवेणी-चंदौली, पावर्ती -मिजार्पुर, वंदना-जौनपुर और यज्ञ नारायण बिहार के बक्सर के निवासी हैं। घटना की सूचना मिलते ही अपर जिलाधिकारी (नगर) वीरेंद्र प्रसाद पांडेय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उचित कार्रवाई का आश्वान दिया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बेहतर इलाज की व्यवस्था करवाने का आदेश दिया।

पांडेय ने बताया कि सभी मरीजों का इलाज वाराणसी के दूसरे अस्पताल में की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच, मामले की जांच कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सिंह ने बताया कि एक मरीज की रोशनी में सुधार हो रहा है, जबकि पांच की आंखों में गंभीर संक्रमण होने के कारण ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। उनका इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों

रचेगा नया इतिहास : जूना अखाड़ा एकसाथ बनाएगा 221 दलित महिलाओं को संत

इलाहाबाद। प्रयाग में लगने वाले कुम्भ 2019 में जूना अखाड़ा 221 दलित महिलाओं को संत बनाएगा। मौनी अमावस्या के पहले इन महिलाओं को संत बनने की दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद इन्हीं महिला संतों में से पांच को महामंडलेश्वर भी बनाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दलित महिलाओं को संत बनाया जाएगा। जूना अखाड़ा के प्रमुख संरक्षक महंत हरि गिरि ने बताया कि इन महिलाओं के अलावा इसी अखाड़े में लगभग तीन सौ दलित व महादलित पुरुष भी संत बनने की दीक्षा ग्रहण करेंगे। 500 है अखाड़े में दलित महिला संतों की संख्या बकौल महंत हरि गिरि देश के अलग-अलग हिस्सों में जूना अखाड़ा के लाखों संत हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कनार्टक, महाराष्ट्र और नेपाल में सभी वर्गों को मिलाकर लगभग सवा लाख महिला संत हैँ। जूना अखाड़े में है आठ दलित महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में बड़ी संख्या में दलित जाति के पुरुष और महिला संत पहले से हैं। इनमें से मात्र आठ को ही महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है जिनमें पांच पुरुष और तीन महिला महामंडलेश्वर हैँ।

संत बनने की प्रक्रिया

संत बनने के पूर्व पुरुष व महिलाओं को मुंडन कराना पड़ता है।

»» कांग्रेस बोल रही भाजपा की भाषा : आप

गृह मंत्री ने उचित कदम उठाने का दिया भरोसा : संजय सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने की मांग पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को कांग्रेस द्वारा नकारने पर कहा है कि कांग्रेस भाजपा की बोली बोल रही है। आप के राज्यसभा सदस्य संजयसिंह ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन द्वारा केजरीवाल की हड़ताल को गैरजरूरी बताने के आरोपों को खारिज करते हुये कहा कि कांग्रेस अपने झूठ को छुपाने के लिये पूर्ण राज्य की मांग पूरी न होने में संवैधानिक मजबूरी बता रही है।

दीक्षित के आरोपों को गलत बताते हुये सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अरूणांचल, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर, पुद्दुचेरी तथा कर्नाटक हर मामले में आप लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस आज भाजपा की भाषा बोल रही है। अधिकारियों के हड़ताल पर होने की बात को कांग्रेस नेताओं द्वारा गलत बताने पर सिंह ने कहा कि क्या माकन को ये पता नहीं की प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्री द्वारा बुलाई गई तैयारी मीटिंग का आईएएस अधिकारियों ने बार-बार बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का तीन महीने से लगातार मंत्रियों द्वारा बुलायी जा रही बैठकों का बहिष्कार करना अगर हड़ताल नहीं है तो इसे और क्या कहेंगे? अजीब बात है, क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? अगर नहीं तो उनसे (एलजी) मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री और उनके मंत्री आतंकवादी हैं? इससे स्पष्ट है कि दिल्ली के उपराज्यपाल गतिरोध को खत्म करने के बजाय बढ़ाना चाहते हैं।

एलजी ने केजरीवाल से मिलने से मना किया : सिंह

दिल्ली सरकार के अधिकारियों की आंशिक ''हड़ताल' को खत्म कराने की आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य मंत्रियों की मांग पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को गृहमंत्री से मुलाकात करने के बाद यह जानकारी दी।

केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के चार मंत्री अधिकारियों की ''हड़ताल' खत्म कराने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर राजनिवास में पांच दिन से अनशन पर बैठे हैं।

संजयसिंह ने कहा कि दिल्ली में जो आईएएस अफसरों की हड़ताल चल रही है और उससे लगातार जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसके बारे में गृहमंत्री को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने सुबह हुई मुलाकात के दौरान गृह मंत्री से मिले सकारात्मक जवाब पर खुशी जताते हुए जल्द ही समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद जताई। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही आप खेमे में माहौल फिर तल्ख हो गया जब उपराज्यपाल बैजल ने संजय सिंह के केजरीवाल से मुलाकात करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। संजय सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय से बताया गया कि मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता। अजीब बात है, क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है? अगर नहीं तो उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री और उनके मंत्री आतंकवादी हैं? इससे स्पष्ट है कि दिल्ली के उपराज्यपाल गतिरोध को खत्म करने के बजाय बढ़ाना चाहते हैं।

राजनिवास में अनशन पर बैठे मंत्री सत्येन्द्र जैन और मनीष सिसोदिया की चिकित्सा जांच के लिये दोपहर बाद डाक्टरों का दल पहुंचने पर आप ने जबरन अनशन तुड़वाने की कोशिश करने का उपराज्यपाल कार्यालय पर आरोप लगाया। संजयसिंह ने अनशनकारियों के साथ अमानवीय बर्ताव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम राजनिवास पहुंच गई है। मनीष सिसोदिया और सतेन्द्र जैन को उठाने की तैयारी हो रही है।

तानाशाही जारी है। इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को सुबह कार्यकर्ताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी कर आगामी 17 जून को पीएम आवास का घेराव कर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। संजय सिंह ने बताया कि पीएम आवास के घेराव की तैयारियों के लिये शाम को आप विधायकों, सांसद और अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलायी गई है।

सूरजकुंड में तीन दिवसीय मंथन शिविर में बीजेपी संगठन महामंत्री रामलाल भी पहुंचे।

शहीद औरंगजेब के जनाजे में अमड़ा जन सैलाब, पिता बोले- आतंकवादियों से लो बदला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान औरंगजेब का पार्थिव शरीर उनके गांव मेंढर तहसील के सलानी गांव पहुंचा। जवान के पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। गांव के लोगों में जवान को खोने के गम के साझ-साथ गुस्सा भी दिखाई दिया। कहां शहीद जवान औरंगजेब परिवार के साथ ईद मनाने के लिए घर लौट रहे थे और घर में भी ईद की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन त्यौहार के दिन के दिन वो आए, पर तिरंगे में लिपटे हुए। उनकी शहादत पर पिता हनीफने सरकार से बदला लेने की मांग की है। बेटे की शहादत पर औरंगजेब के पिता हनीफने कहा कि उनका बेटा एक बेटा शहीद हो गया है लेकिन उनका बड़ा बेटा भी फौज में है। जवान के पिता ने आगे कहा कि हम सब देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। साथ ही मोहम्मद हनीफने केंद्र सरकार को कहा कि मोदी सरकार आतंकियों को मारकर बेटे की शहादत का बदला ले वरना वह खुद बदला लेंगे।

»» दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, गलतफहमी न पालें केजरीवाल : कांग्रेस

शीला ने केजरीवाल को संविधान पढ़ने की सलाह दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें सबसे पहले संविधान पढ़ना चाहिए।

इसके बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री व संसद से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री की भूमिका संविधान में स्पष्ट तौर पर परिभाषित है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि क्यों आप नेता सोमवार से उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में धरना दिए हुए हैं। दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसके पीछे उनकी (केजरीवाल) क्या मंशा है? उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर शर्मिन्दा हैं कि उपराज्यपाल कार्यालय में धरने की तस्वीरों को एक मुख्यमंत्री इंटरनेट पर जारी कर रहे हैं।

अपनी और आम आदमी पार्टी सरकार की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वह जब 1998 में मुख्यमंत्री बनी थीं तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी तथा उनके बीच कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग की थी लेकिन कभी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और शीला दीक्षित ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करते हुए कहा कि केजरीवाल को यह बात समझनी चाहिए कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यदि वह यह सोचते हैं कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसा शासन मॉडल चला सकते हैं तो वह गलत समझ रहे हैं। पहले उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए।

यदि उन्हें लगता है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है तो उन्हें मोदी जी एवं संसद से संपर्क करना चाहिए।

बहरहाल उन्होंने यह भी कहा कि लोग धरने के पीछे की राजनीति समझते हैं क्योंकि ''वे बेवकूफ नहीं हैं।

' बार-बार यह बहाना बनाने की बजाय कि उनके पास अधिकार नहीं है उन्हें विकास कायरे पर ध्यान देना चाहिए। माकन ने कहा कि यदि आप दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और सचिवों के कार्यालयों में ताला लगा देंगे तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नौकरशाही आपके साथ सहयोग करेगी।

हमने 15 साल के अपने शासन के दौरान नौकरशाही के साथ कोई टकराव नहीं किया। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगी, माकन ने कहा कि हम राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं है।

हम दिल्ली की निर्वाचित सरकार को हटाए जाने के पक्ष में नहीं हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेगी, उन्होंने कहा कि वह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आप के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता।

संपादकीय

वाटर इंडेक्स में धड़ाम

नीति आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद कम से कम इस बात पर संदेह नहीं रह गया कि भारत अपने इतिहास के सबसे भयावह जल संकट के दौर में है और यह भी कि हालात को इस कदर बिगाड़ने में अकर्मण्य सरकारी तंत्र के साथ हमारी भी बड़ी भूमिका है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को तो युद्ध स्तर पर नई शुरुआत करनी ही होगी, हमें भी अपने-अपने स्तरों पर तत्काल सक्रिय हो जाने की जरूरत है। नीति आयोग के जल प्रबंधन इंडेक्स के अनुसार, देश के तकरीबन 60 करोड़ लोग पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं, और दो लाख लोग हर साल सिर्फ इस कारण मर जाते हैं कि उनकी पहुंच में पीने योग्य पानी नहीं होता। 75 फीसदी घरों में पीने का पानी नहीं है और देश का करीब 70 फीसदी पानी पीने योग्य नहीं है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर है। रिपोर्ट आगाह करती है कि समुचित प्रबंधन न हुआ, तो 2030 तक चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि तब तक पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो चुकी होगी। कुल मिलाकर, स्थिति भयावह है और बात कटते वनों, नव वनीकरण में कोताही, अंधाधुंध निर्माण के लिए जल दोहन और शहरीकरण में जल स्रोतों के खत्म होते जाने के सियापे से आगे जा चुकी है। तमाम और कारण भी हैं। आज भी हम खेती के लिए पानी के तार्किक उपयोग वाले सिंचाई के उन्नत इंतजाम में पीछे हैं, जो बड़ी समस्या है। अंधाधुंध शहरीकरण में उगते कंक्रीट के जंगलों ने पानी की पारंपरिक रिचार्जिंग तो कम की ही, पारंपरिक जल स्रोतों को खत्म ही कर दिया। इन्हें किसी भी सूरत में वापस लाना होगा। नदियों, धाराओं व तालाबों में रसायन और कचरा डालने पर दिखावटी सख्ती हुई, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। शहरी उपभोक्ता, कृषि क्षेत्र व उद्योगों के बीच पानी के बंटवारे का असंतुलन भी हम नहीं ही दूर कर पाए। इस मामले में सरकारी तंत्र की नाकामी सबसे ऊपर है। पर सच यह है कि बहुत छोटे दिखने वाले उपाय अमल में लाकर भी इस बड़े संकट को छोटा किया जा सकता था। आंकड़े बताते हैं कि महज घरों के यूरीनल में हर बार फ्लश चलाने से बचा जाए या वाटर फ्री यूरीनल का प्रयोग किया जाए, तो हर घर से, हर दिन इतना पानी बचेगा कि सौ फ्लैट वाला एक अपार्टमेंट हर दिन अकेले कम से कम सात हजार लीटर पानी बचा सकता है। कल्पना करें कि यह प्रयोग अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जल संकट से जूझते शहरों में ही क्यों, हर शहर के हर अपार्टमेंट, दफ्तर और स्कूल में अनिवार्य हो जाए, तो नतीजे कितने सुखद होंगे? मानना होगा कि जब हम अपार्टमेंट की राह चल ही पड़े हैं, तो जरूरी है कि वह संस्कृति भी अपनाएं, जो इस राह को सुखकर बनाए। सबसे ज्यादा जल दोहन यहीं से हुआ है, तो सबसे पहली नई शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। हर अपार्टमेंट यदि किचन और बाथरूम के पानी का संचय कर उसके शोधन और फिर से इस्तेमाल की व्यवस्था कर ले, वाटर फ्री यूरीनल का प्रयोग शर्त बन जाए, तो नतीजे कितने प्रीतिकर होंगे, सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मानने में गुरेज नहीं कि जिन हालात की ओर हम खुद को धकेल रहे हैं, उसमें कल को हमारा भी कोई शहर केपटाउन बन जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। शिमला जैसे शहर तो उस दरवाजे पर खड़े ही हैं।.

गंभीर होता जल संकट

भारत में जल संकट की समस्या आने वाले कुछवर्षों में और अधिक विकराल हो सकती है। नीति आयोग की जल-प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट का सार यही है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के करीब साठ करोड़ लोग पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं, और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से प्रति वर्ष जल-जनित बीमारियों की वजह से करीब दो लाख लोगों की मौत हो रही है। ताज्जुब तो इस बात पर है कि आजादी के सत्तर सालों बाद भी पचहत्तर फीसदी घरों में पीने का पानी मुहैया नहीं है अर्थात उन्हें पेयजल के लिएदूर-दूर तक जाना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि लोकप्रिय जनकल्याणकारी सरकारों का जल संकट के प्रति नजरिया उदासीन रहा है। हालांकि जल संकट कोईनई समस्या नहीं है। देश के जागरूक सामाजिक संगठन दशकों से जल संकट का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि देश में सत्तर फीसदी पानी पीने लायक ही नहीं है। शहरों और कस्बों में जिनके पास पर्याप्त पैसा है, वे खरीद कर बोतलबंद पानी पीते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत जैसे गरीब देशमें हर कोईबोतलबंद पानी खरीद नहीं सकता। तो क्या इन्हें प्रदूषित पानी पीने के लिए इनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर लोकप्रिय सरकारें अपने नागरिकों को शुद्ध पेयजल भी मुहैया नहीं करा सकती तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। भारत में फिलहाल प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1544 क्यूबिक मीटर है। इस स्थिति को जल की कमी की चेतावनी के रूप में देखा जाता है। अगर यह उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे आ जाए तो जल संकट माना जाता है। देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले एक दशक में भारत जल संकट-ग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह भूजल का बेतरतीब दोहन भी है। जल राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लिहाजा राज्य सरकारों की ओर से जल के महत्व के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। दरअसल, जल संकट प्राकृतिक और मानव-निर्मित, दोनों है। जल का समुचित प्रबंधन करके हम जल संकट का समाधान निकाल सकते हैं। सरकार को जल संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि पानी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। लिहाजा हमें जीवन में जल के महत्व को समझते हुएइसकी बर्बादी को रोकने के उपायों पर भी ध्यान देना होगा।

कटाक्ष/ कबीरदास

काम और हड़ताल

अच्छे दिन लाने की हम नहीं कहते, पर केसरिया भाइयों की सरकार ने एक वादा सौ टका पूरा किया है। जो-जो पहले सत्तर साल में नहीं हुआ था, अब हो रहा है। हो सकता है कि अच्छे दिनों का आना भी इसी वादे के चक्कर में टल रहा हो। पहले कभी अच्छे दिन आए हों तो! खैर! जो पहले नहीं हुआ, वही-वही होने का आलम तो यह है कि शब्दों के अर्थ तक वह नहीं रहे हैं, जो पिछले सत्तर साल में थे। वर्ना चार साल पहले जिन्हें पक्का वादा बताया जा रहा था, यूं पककर जुमला कैसे बन जाते?यही किस्सा काम और हड़ताल का है। पहले काम, काम होता था, हड़ताल, हड़ताल। दोनों अलग-अलग रहते थे बल्कि उनमें दुश्मनी मानी जाती थी। काम होता था तो हड़ताल नहीं होती थी। हड़ताल होता थी, तो काम ठप होने का शोर मच जाता था। पर अब नहीं। मोदी जी के राज में नहीं। हमारी न मानो तो केजरीवाल साहब से पूछो। उनकी तरफ से देखो तो दिल्ली के आला अफसर हड़ताल पर नजर आएंगे। वह भी आज-कल नहीं, पूरे चार महीने से। पर एलजी साहब की तरफ से देखो तो अफसर बदस्तूर काम पर हैं। वैसे हड़ताल को ही काम मानने के मामले में, केजरीवाल एंड कंपनी भी किसी से पीछे नहीं है। कई दिन से हड़ताल कर के एलजी के घर पर धरने पर बैठे हुए हैं, पर केसरिया भाइयों के इसे हड़ताल कहने को झुठला रहे हैं। धरने पर ही दफ्तर की फाइलों पर काम कर के दिखा रहे हैं। खैर, जैसे को तैसा जवाब देने के लिए केसरिया भाई भी धरने पर बैठ गए हैं, सीएम के दफ्तर में। पर वे भी इसे जवाबी हड़ताल मानने को तैयार नहीं हैं और खुद को काम पर बता रहे हैं। कहते हैं-विपक्ष का तो यही काम है! वैसे अफसर अगर मंत्रियों की, सरकार की बुलायी बैठकों में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या अफसरों का काम बैठकों में जाना है? अफसरों के बिना अगर तीन महीने सरकार चल सकती है, तो पांच साल क्यों नहीं? और हां! अगर दिल्ली की सरकार चल सकती है, तो देश की सरकार क्यों नहीं? क्या अफसरमुक्त भारत का भी वादा था?

पूर्ण राज्य के लिए अपूर्ण आंदोलन

बुंदा करात सदस्य माकपा पोलित ब्यूरो

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनता द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उप-राज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में धरना पर बैठने के असाधारण कदम ने भी केंद्र सरकार पर यह असर नहीं डाला है कि वह हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि उप-राज्यपाल मुनासिब बातचीत शुरू करें और मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए तर्कसंगत मसलों पर गौर करें। मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात तो छोड़िए, उप-राज्यपाल ने बातचीत करने से ही इनकार कर दिया है।

इस संदर्भ में जो सबसे अहम मुद्दा है, वह है दिल्ली सरकार के अफसरों का निर्वाचित सरकार के साथ सहयोग और अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संगठन की प्रवक्ता मनीषा श्रीवास्तव ने दावा किया है कि अधिकारी हड़ताल पर नहीं हैं और उन्होंने न सिर्फ बजट तैयार किया, बल्कि विधानसभा में सवालों के जवाब भी तैयार किए। मगर वह यह भी स्वीकार करती हैं कि 'अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा बुलाई गई नियमित बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं।' यानी दूसरे शब्दों में वे अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति आईएएस अधिकारियों की यह अदावत उस घटना की परिणति है, जिसमें फरवरी महीने में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दो आप विधायकों पर आरोप लगाया कि केजरीवाल की मौजूदगी में उन दोनों ने मुख्यमंत्री आवास में उनसे मार-पीट की। मुख्यमंत्री और आप विधायकों ने इस आरोप का खंडन किया। लेकिन मामला बिगड़ता गया। आप नेतृत्व इस विवाद से बेहतर तरीके से निपट सकता था, पर वह ऐसा न कर सका, और यही वजह है कि इस मामले में उसे जनता का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। हम सब जानते हैं, दिल्ली पुलिस उप-राज्यपाल के मातहत है और उसने इस संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज की, आरोपी विधायकों को गिरफ्तार किया गया और करीब दो हफ्ते पहले वे जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। बहरहाल, मामला अदालत में है। इसके बावजूद यह साफ है कि अफसरों का पूरा समूह राज्य सरकार की नाफरमानी कर रहा है, क्योंकि वे उप-राज्यपाल और केंद्र सरकार की सरपरस्ती में हैं।

जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपूर्व जीत हासिल की है, केंद्र सरकार ने उप-राज्यपाल के दफ्तर के जरिए उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं गंवाया है। विधानसभा चुनाव के चंद महीने बाद ही मई 2015 में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत विभिन्न सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का दिल्ली सरकार का अधिकार उससे ले लिया, साथ ही एंटी-करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण भी केंद्र ने राज्य सरकार से ले लिया। राज्य सरकार को हासिल सीमित स्वायत्तता के भीतर भी इस अघोषित जंग ने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया कि वे यह जान लें कि उनका असली बॉस कौन है?

दिल्ली सरकार के अधिकारों के इस अतिक्रमण के खिलाफ केजरीवाल सरकार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त 2016 में जो फैसला दिया, उससे केंद्र के कदम को वैधता मिल गई। अदालत ने अपने फैसले में उप-राज्यपाल को 'प्रशासकीय मुखिया' माना और निर्वाचित सरकार के कदमों को 'असांविधानिक व गैर-कानूनी' करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मौजूदा 'वैधानिक' स्थिति यही है। इस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी कानून बनाने की मांग काफी प्रासंगिक है। यह मांग नई भी नहीं है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान में भाजपा ने जो अहम वादे किए थे, उनमें एक यह था कि यदि वह सत्ता में आई, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। भाजपा ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें जीतीं, तब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्द्धन ने कहा था कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के सामने हम पहला मुद्दा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का उठाएंगे।' चार वर्ष बाद मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान क्या है? बकौल मनोज तिवारी, 'मौजूदा संघीय ढाचा इतना लचीला है कि दिल्ली की विकास संबंधी तमाम जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं।'

वाजपेयी सरकार के दौरान 2003 में तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने संबंधी एक विधेयक संसद में पेश किया था। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान यह विधेयक निरस्त हो गया। मगर जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य विधानसभा में लगभग वैसा ही विधेयक पेश किया, तो भाजपा ने मजबूती के साथ उसका विरोध किया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें उसे कांग्रेस का साथ मिल रहा है। कांग्रेस की राज्य इकाई तो लगता है, जैसे संतुलन साधना भी भूल गई है। केंद्र सरकार की एकतरफा कार्रवाइयों और सहयोगपूर्ण संघवाद का मजाक बनाए जाने की आलोचना में वह एक शब्द कहे बिना आम आदमी पार्टी की सरकार की खिंचाई में जुटी रहती है।

केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी अधिकारों के इस फुटबॉल में दिल्ली की जनता पिस रही है, जिसकी चिंताओं व अधिकारों को इधर से उधर धकेला जा रहा है। उसके प्रति न तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है और न राज्य सरकार। दोनों एक-दूसरे पर वादे से मुकरने के आरोप मढ़ती रहती हैं। जनता के प्रति जिम्मेदारी किसी भी सुशासन की बुनियाद होती है। लेकिन दिल्ली की मौजूदा व्यवस्था में, जहां केंद्र सरकार अपने 'प्रशासनिक मुखिया' के लिए अधिकारियों का चयन करती है, कुछ-कुछ औपनिवेशिक युग जैसा ही है, जब वायसराय के पास सारे अधिकार होते थे, मगर वह जवाबदेह सिर्फ सम्राट के प्रति होता था। दुर्योग से पूर्ण राज्य संबंधी आम आदमी पार्टी का मौजूदा आंदोलन संकीर्ण है, जबकि जिस तरह उसने इस मसले को उठाया है, उसे नागरिकों के व्यापक समुदाय को भी इससे जोड़ना चाहिए था। फिर भी, दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की लोकतांत्रिक मांग का वाम दल लंबे अरसे से समर्थन करते रहे हैं और इसका समर्थन किया भी जाना चाहिए। यह न सिर्फ दिल्ली के बाशिंदों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए अहम है, जो देश के संघीय ढांचे में भरोसा करता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

> दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच राज्य के दर्जे को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें देश की राजधानी के लोग बेवजह पिस रहे हैं।

राज्यनामा

अब आंदोलन बूते सियासी जंग

हरीश लखेड़ा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तीन मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय पर एक सोची-समझी रणनीति के तहत धरने पर बैठे। दिल्ली में वे पहले मुख्यमंत्री हैं जो राजनिवास पर धरने पर बैठे। इससे पहले वे दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए इतने समय बाद भी वे अपनी एक्टिविस्ट वाली छवि से आज भी बाहर नहीं निकल पाए हैं।

अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं व उसके भी अगले साल विधानसभा के। केंद्र में राज कर रही भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पहले ही मिशन 2019 की तैयारी में जुट चुके हैं। दूसरी ओर पंजाब, गोवा, दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों से लग रहा था कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) लगातार सिमट रही है। भाजपा समेत विभिन्न दलों के नेताओं से माफी मांगने से केजरीवाल की लड़ाकू छवि भी कमजोर होने लगी थी। इसके अलावा कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद देशभर में जिस तरह से भाजपा विरोधी गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई, उसमें दिल्ली कांग्रेस के विरोध के चलते केजरीवाल को अपनी जगह नहीं दिख रही थी। ऐसे में केजरीवाल अपने लिए एक और धरना-प्रदर्शन के लिए जमीन तलाशने लगे।

केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली-पानी में सब्सिडी देकर बिल बढ़ने नहीं दिए। लेकिन वे अपनी छवि को कुशल मुख्यमंत्री की नहीं बना पाए। दिल्ली में उनके कार्यकाल में एक भी बड़ी परियोजना शुरू होती नहीं दिखी। यह भी कह सकते हैं कि ज्यादातर मोर्चों पर वे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के सामने उन्नीस ही दिख रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उपराज्यपाल के दफ्तर पर धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान ही किया है।

केजरीवाल लगातार जनता को जताने कोशिश करते रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार उपराज्यपाल के जरिए उन्हें काम नहीं करने दे रही है। इसके लिए उनके पास मजबूत तर्क भी हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के 17 विधायकों के खिलाफ पुलिस व सीबीआई ने जो भी मुकदमे दर्ज किए, उनमें से लगभग सभी में अदालत में वे टिक नहीं पाए। राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निरोधी विभाग छीन कर भी केंद्र ने केजरीवाल के आरोपों पर मुहर ही लगाई है। तब से इस विभाग ने सिर्फ विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

अब राजनिवास पर धरना देने का मामला मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मंत्रियों व विधायकों की मारपीट से जुड़ा है। दिल्ली के अफसर आरोप लगाते हैं कि वे बैठकों में अफसरों से दुर्व्यवहार करते हैं। अब दिल्ली के आईएएस समेत अन्य अफसर मुख्य सचिव से मारपीट की घटना के विरोध में मंत्रियों की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। वे कैबिनेट जैसी जरूरी बैठक में तो जाते हैं लेकिन मंत्रियों के साथ उनका संवाद लिखित तौर पर होता है। इसी को केजरीवाल अफसरों की हड़ताल कहते हैं। जबकि आईएएस अफसरों की एसोशिएशन कह चुकी है कि जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे वे ऐसे ही काम करेंगे। दूसरी ओर केजरीवाल व उनके मंत्री कहते रहे हैं कि अफसरों ने भी उनके मंत्री की पिटाई की।

केजरीवाल की मांग है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

दरअसल, दिल्ली की जनता से किए वादों में से अभी कई पूरे करने बाकी हैं। केजरीवाल ने बिजली और पानी में सब्सिडी देकर दिल्ली की बड़ी आबादी को राहत दी है। उनके मोहल्ला क्लीनिक की भी देश-दुनिया में तारीफ हुई है। सरकारी स्कूलों का भी उन्होंने कायाकल्प किया है। डीटीसी बसों में बुजुर्गों, स्कूल-कालेज के छात्रों को मुफ्त यात्रा व महिलाओं को भी राहत दी है। शिक्षा के लिए लोन व स्किल डेवलेपमेंट के लिए उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। हालांकि दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए लगने वाले 15 लाख सीसीटीवी अभी तक नहीं लग पाए हैं। महिला सुरक्षा दल का गठन व सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वाईफाई नहीं दे पाए हैं। मजबूत लोकायुक्त भी नहीं बन पाया है।

हालांकि केजरीवाल ने सीलिंग और मेट्रो का किराया न बढ़ाने के फैसलों का विरोध करके भाजपा को पहले से ही मुश्किल में डाल रखा था, अब दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करके केंद्र की मोदी सरकार को भी संकट में डाल दिया है। दिल्ली विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी आज भी उपराज्यपाल के नियंत्रण में है। कानून और व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे अहम विषय उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास हैं। ऐसे में बड़े अफसर भी उनकी सुनते कम ही हैं। यह भी सच है कि दिल्ली में हमेशा ही उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर तनातनी रही है।

बहरहाल, केजरीवाल का यह चुनावी दांव सटीक जगह लगा है। अब तक सुस्त पड़ी आप के कार्यकर्ता अब फिर से मैदान में उतर आए हैं। उन्हें विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। वे जिन वादों को पूरा नहीं कर पाए थे, उनसे बचने का बहाना भी मिल गया है कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है।

पाकिस्तान

बॉलीवुड के लिए बेताबी क्यों?

मोहम्मद शहजाद

भारत-पाक के दरम्यान फिल्मी प्रेम प्रसंग काफी पुराना है। अब तक ये काफी हद तक एकतरफा रहा है। अलबत्ता इधर हमारे युवाओं के दिलों में भी पाकिस्तानी अदाकारों के लिए मोहब्बत की कोंपलें फूटने लगी हैं, लेकिन इसका दायरा अभी सीमित है। इसके बरक्स बॉलीवुड की फिल्मों और हीरो-हीरोइनों के प्रति सरहद उस पार काफी दीवानगी है। मुंबइया फिल्मों के आगे पाकिस्तानियों को अपने अदाकारों के चेहरे भी बेगाने लगते हैं। पाकिस्तान ने इस पर कई बार पहरा बिठाने की कोशिशें की। मगर ''इश्क व मुश्क' की तरह इसे कभी छुपाया नहीं जा सका। आगामी ईद और बकरीद के अवसर पर पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर लगाया गया अस्थाई प्रतिबंध इसकी एक नजीर भर है। महज एक हफ्ते के भीतर ही पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल, पाकिस्तान ने इन त्योहारों के दो दिन पहले और दो हफ्ते बाद तक बॉलीवुड की फिल्मों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके पीछे स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा देने की दलील दी गई। किंतु फिल्म वितरकों और दीगर सिनेमा व्यावसायियों के दबाव के आगे पाकिस्तानी सरकार को झुकना पड़ा। अब पाकिस्तान ने अपने प्रतिबंध की मियाद कम करके महज एक सप्ताह कर दी है। पाकिस्तान ने यह कदम भारत के साथ संबंध सुधारने या फिर विास बहाली के मकसद से नहीं उठाया है बल्कि यह पूरी तरह आर्थिक नफा-नुकसान के मद्देनजर लिया गया फैसला है। दरअसल, पाकिस्तान में फिल्मों का कारोबार बहुत हद तक बॉलीवुड पर निर्भर है और उसमें 60-75 प्रतिशत बॉलीवुड की हिस्सेदारी है।

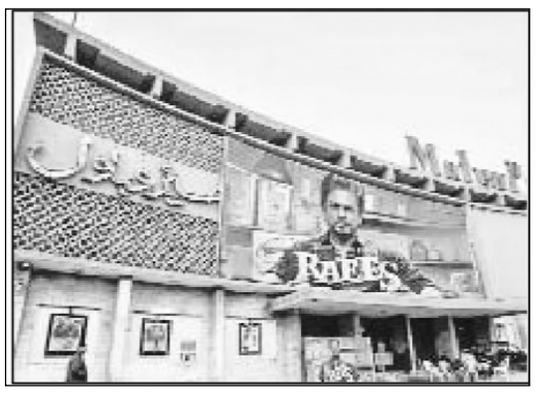

जब भी वहां पर मुंबइया फिल्मों को बैन किया जाता है तो सिनेमाघरों में दर्शकों की मौजूदगी केवल 17-40 फीसद ही रह जाती है। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान को फिल्मी कारोबार का तीन-चौथाई राजस्व बॉलीवुड की फिल्मों से प्राप्त होता है। बॉलीवुड पर वहां बैन की सूरत में सप्ताहांत पर लगभग एक करोड़ रु पये के राजस्व की हानि होती है। पाकिस्तानियों पर बॉलीवुड के खुमार की ही देन है कि इधर वहां फिल्मों के कारोबार में लोग धड़ल्ले से निवेश करने लगे हैं। इसके नतीजे में हालिया वर्षों तक एक भी मल्टीप्लेक्स न होने वाले पाकिस्तान में 2015-16 तक इनकी संख्या 100 तक पहुंच गई थी। लाहौर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल एम्पोरियम ने भी अपने 9 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स की योजना को घटा कर तीन स्क्रीन कर दिया था। पाकिस्तान के फिल्मी आयातक और वितरक इस तल्ख हकीकत से भलीभांति परिचित हैं कि भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने से उनकी स्वदेशी फिल्मों को बढ़ावा मिलने से रहा। कारण पाकिस्तानी फिल्मों का बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले काफी स्तरहीन होना है। ऐसे में पाकिस्तानी दर्शकों को जबरन सिनेमाहॉल तक लाना संभव नहीं है, जबकि हिन्दुस्तानी फिल्में देखने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर सिनेमाहॉल में बॉलीवुड की फिल्में उन्हें देखने को नहीं मिलेंगी तो वे पाइरेटेड डीवीडी पर इसे देख लेंगे। शाहरुख खान की फिल्म ''रईस' इसका हालिया उदाहरण है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों देशों के मध्य व्याप्त होने वाले राजनीतिक तनाव का खामियाजा आखिर दशर्क क्यों भुगतें? फिर जब पाकिस्तानियों को बॉलीवुड की फिल्में देखनी ही हैं तो उसका लाभ पाइरेटेड डीवीडी का गैर-कानूनी कारोबार करने वालों को क्यों मिले? अब तो वैसे ही इस फिल्मी मोहब्बत की आग दोनों तरफ लगी हुई है। अब तक महज पाकिस्तानी गीतकारों और गायकों की हिन्दुस्तानियों की पसंद अब पाकिस्तानी अदाकारों तक जा पहुंची है। यही नहीं अब तक बॉलीवुड की कमाई का मामूली हिस्सा जोड़ने वाला पाकिस्तान उसे 2 अरब डॉलर की सालाना आमदनी देने लगा है। फिर बात महज माली घाटे और फायदे की नहीं है बल्कि उस संयुक्त संस्कृति की है, जो सरहद के दोनों तरफ के लोगों को आपस में जोड़ती है। हम फिल्म समेत किसी भी कला को सरहदों में कैद नहीं कर सकते हैं। काबिलेजिक्र है कि 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद भी पाकिस्तान में बॉलीवुड की फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान में हिन्दी फिल्मों की दीवानगी कम नहीं हुई और लोग अवैध तरीके से वीसीआर आदि के जरिए इसे देखते रहे। 80 के दशक में तो पाकिस्तान भारतीय फिल्मों की नकल करने की नाकाम कोशिश करने लगीं। ऐसे में बेहतर यही है कि पाकिस्तान बॉलीवुड पर प्रतिबंध लगाने की बजाए उससे प्रतिस्पर्धा करे और उसके जैसा बनने की कोशिश करे।

चीन का पलटवार, अमेरिकी उत्पादों पर लगाया अतिरिक्त शुल्क

बीजिंग (एजेंसी)

चीन ने ' जैसे-को-तैसा' कहावत की तर्ज पर 50 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने की शनिवार को घोषणा की। अमेरिका ने कल ही 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसी के साथ दुनिया की इन दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच गया है और एक तरह से व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बौद्धिक संपदा की चोरी और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों का हवाला देकर चीन से आयातित 50 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। चीन ने जवाबी कदम की चेतावनी दी थी। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि चीन की सरकार ने 50 अरब डॉलर के 659 अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया है। इसने कहा कि सरकार ने उन उत्पादों की सूची भी जारी की है जिनपर ये अतिरिक्त शुल्क लगेंगे।

चीन के सीमा शुल्क आयोग ने जारी बयान में कहा कि 34 अरब डॉलर के 545 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क 6 जुलाई से प्रभावी होंगे। इनमें कृषि उत्पाद व वाहन आदि शामिल हैं। शेष 114 उत्पादों जिनमें रासायनिक उत्पाद, चिकित्सकीय उपकरण और ऊर्ज़ा उत्पाद शामिल हैं , पर शुल्क लगाने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अमेरिका ने शुक्रवार को घोषणा किया था कि छह जुलाई से 34 अरब डॉलर के चीनी उत्पाद पर अतिरिक्त शुल्क लगेंगे और शेष 16 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क लगाने के बारे में अभी समीक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने चीन द्वारा बदले की कार्यवाही करते हुए कदम उठाने की स्थिति में अतिरिक्त 100 अरब डॉलर के चीनी उत्पाद पर भी शुल्क लगाने की चेतावनी दी थी।

चीन के एक अधिकारी ने नाम जाहिर किए बिना इस बाबत कहा कि चीन ने अमेरिका के इस बयान का संज्ञान लिया है। चीन इस बारे में जवाबी कदम उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। ट्रंप ने सबसे पहले मार्च में कहा था कि अमेरिका चीन के 50 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क लगाएगा। चीन द्वारा

जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद ट्रंप ने चीन के 100 अरब डॉलर के अतिरिक्त उत्पादों पर शुल्क लगाने की बात की थी। बाद में मई के मध्य में दोनों देशों ने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी। हालांकि महज 10 ही दिन बाद अमेरिका ने कहा था कि वह शुल्क लगाएगा।

वैश्विक संकेतों से सोना 32,000 रुपये से नीचे फिसला

नयी दिल्ली। मौजूदा स्तर पर स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग में गिरावट तथा वैश्विक स्तर पर कमजोरी के रुख के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत आज 390 रुपये की गिरावट के साथ 32,000 रुपये के स्तर से नीचे 31,800 रुपये प्रति दस ग्राम रह गई। चांदी की कीमत भी 1,050 रुपये की गिरावट के साथ 42,000 रुपये के स्तर से नीचे 41,350 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। बाजार सूत्रों ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की ताजा आशंका के बावजूद सटोरियों ने अपने जमा सौदों की कटान की जिससे वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट का रुख कायम हो गया। वैश्विक स्तर पर कल न्यूयॉर्क में सोना 1.77 प्रतिशत गिरकर 1,278.90 डॉलर प्रति औंस रह गया। जबकि चांदी भी 3.44 प्रतिशत की हानि के साथ 16.54 डॉलर प्रति औंस रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 390 - 390 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 31,800 रुपये और 31,650 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। कल के कारोबार में सोने में 330 रुपये की तेजी आई थी। हालांकि, आठ ग्राम की गिन्नी की कीमत 24,800 रुपये पर अपरिवर्तित रही। सोने की तरह चांदी तैयार की कीमत भी 1,050 रुपये गिरकर 41,350 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। जबकि चांदी साप्ताहिक डिलिवरी के भाव 1,295 रुपये की हानि के साथ 40,200 रुपये प्रति किलोग्राम रह गये।

साउथ इंडियन बैंक की प्रतिभूतियों के जरिये 520 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र का साउथ इंडियन बैंक अपनी कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए शेयरों व ऋणपत्रों के जरिये 520 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रहा है। बैंक के निदेशक मंडल की बैठक 11 जुलाई को होगी जिसमें पूंजी जुटाने के बारे में चर्चा की जाएगी। बैंक ने कहा कि इनमें से 20 करोड़ रुपये की राशि शेयर पूंजी के जरिये जुटायी जाएगी जबकि 500 करोड़ रुपये ऋणपत्रों के जरिये जुटाये जाएंगे। बैंक ने कहा कि ऋणपत्रों में वह दीर्घावधि के ढांचागत संरचनात्मक बांड या अन्य प्रतिभूतियां ला सकता है।

बैंक ने 31 मार्च 2018 तक ऋणपत्र जारी कर 490 करोड़ रुपये जुटाये हैं जिसे पिछले साल 11 जुलाई को हुई वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिली थी।

कार्बन फाइबर इकाई में निवेश कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीजी

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) एयरोस्पेस और रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक कार्बन फाइबर विनिर्माण इकाई में निवेश कर रही है। यह देश की अपनी तरह की पहली इकाई है। इसमें कंपनी कम लागत वाले मॉड्यूलर शौचालय व घर के साथ साथ विंडमिल ब्लेड और रोटर ब्लेड आदि के लिए कंपोजिट्स उत्पाद भी बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस पहल में किए जा रहे निवेश का ब्यौरा तो नहीं दिया है लेकिन अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसने प्लास्टिक और धातु उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के 3 डी प्रिंटिंग के लिए क्षमताएं विकसित की हैं। इसमें कहा गया है, 'आरआईएल देश की पहली व सबसे बड़ी कार्बन फाइबर उत्पादन इकाई में निवेश कर रही है ताकि भारत की एयरोस्पेस व रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।' कंपनी ने पिछले साल केमरोक इंडस्ट्रीज की आस्तियों का अधिग्रहण किया था ताकि कंपोजिट कारोबार में उतर सके। कंपनी ग्लास व कार्बन फाइबर रिइनफोर्सड पालीमर (एफआरपी) जैसे थर्मोसेट कंपोजिट पर ध्यान दे रही है।

इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने बांड के जरिये जुटाये 2,318 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने निजी नियोजन आधार पर बांड जारी कर 2,318.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह कंपनी की 24,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना का हिस्सा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने दिसंबर 2017 में सुरक्षित, विमोच्य, गैर-परिवर्तनीय बांड के जरिये 24,000 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की थी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ''कंपनी ने 15 जून को 10-10 लाख रुपये के बांड जारी कर 2,318 करोड़ रुपये जुटाये। यह बांड की 17 वीं किस्त थी।''

अब ईरान से तेल नहीं खरीद पाएंगे

नई दिल्ली। अमेरिका की ओर से इराक पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद से भारतीय तेल कंपनियों को ईरान से तेल खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तेल के भुगतान की व्यवस्था संभालने वाले भारतीय स्टेट बैंक ने तेल रिफाइनरियों को जानकारी दी है कि नवम्बर से यूरो में भुगतान करना बंद हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि ईरान पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभावी होने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गत माह ईरान ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पीछे हट गया था। इसके विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 180 दिन में ईरान पर पुनःप्रतिबंध प्रभावी बनाने का एलान कर दिया था। इसके बाद से ही केन्द्र सरकार यूरोपीय देशों से इस बारे में बात करके इस समस्या का हल निकालने का प्रयास कर रही है। इस प्रयास में लगी हुई कि ईरान से तेल आयात करने का काम आगे लगातार जारी रहे। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं।

टीसीएस की शेयर पुनर्खरीद योजना: शेयरधारकों को 16,000 करोड़ रुपये की पेशकश

मुंबई (एजेंसी)।

देश की प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने 16,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की। यह फैसला अधिशेष पूंजी शेयरधारकों को लौटाने की उसकी दीर्घकालिक पूंजी आवंटन नीति का हिस्सा है। इस पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 1.99 प्रतिशत या 7.61 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद की जाएगी। इन शेयरों को 2,100 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर वापस खरीदा जाएगा। टीसीएस ने पिछले वर्ष भी इसी तरह 16,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद की थी। पुनर्खरीद योजना की घोषणा के साथ ही बंबई शेयर बाजार पर बाद के कारोबारी समय में कंपनी के शेयर 3 प्रतिशत चढ़कर अब तक उच्चतम स्तर 1,849 रुपये पर पहुंच गए। साथ ही बाजार पूंजीकरण भी 7.06 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अंत में 2.75 प्रतिशत चढ़कर 1,841.45 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने शेयरों की पुनर्खरीद के लिए प्रीमियम से 15 प्रतिशत अधिक की पेशकश की है। कंपनी शेयरों को 2,100 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर वापस खरीदेगी। टीसीएस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गोपीनाथन ने 50 वीं सालाना आम बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'कंपनी के लिए पूंजी आवंटन नीति सर्वोपरि है। हम हमेशा शेयरधारकों को लाभ देने में विश्वास रखते हैं। हमने शेयरधारकों के भुगतान में लगातार वृद्धि की है।'

बैठक में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जब पुनर्खरीद के फैसले के बारे में बताया तो शेयरधारकों ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शेयर पुनर्खरीद प्रक्रिया के सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पहले, टीसीएस ने शेयर बाजार को बताया, '... आज आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी के 7.61 करोड़ इक्विटी शेयरों के पुनर्खरीद के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है... इसका मूल्य 16,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।'

ब्रिटेन की कोर्ट ने माल्या से कहा, भारतीय बैंकों को लागत चुकाओ

लंदन (एजेंसी)।

ब्रिटेन की एक अदालत ने संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या से कहा है वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम 2,00,000 पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपए) का भुगतान करे। ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ पिछले माह माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था।

इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कोर्ट की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है। इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे।

मामले की जानकारी रखने वाले एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया कि बैंक की लागत का भुगतान किया जाए। मानक आदेश है कि अगर सम्बद्ध पक्ष भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर सहमत नहीं हुए तो

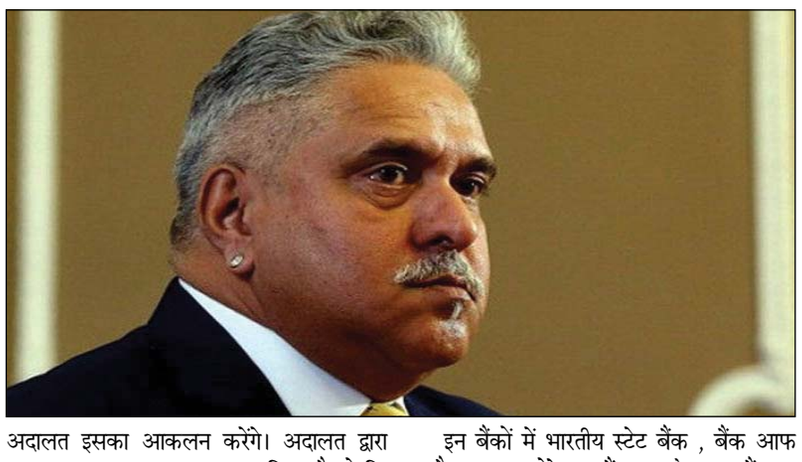

अदालत इसका आकलन करेंगे। अदालत द्वारा आकलन का लागत एक अलग प्रक्रिया है जो कि विशेष जज (लागत) के समक्ष अन्य अदालती सुनवाई के साथ समाप्त होगी।

लेकिन इस बीच माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2,00,000 पौंड का भुगतान करना ही होगा।न्यायाधीश हेनशॉ ने आठ मई को अपने फैसले में माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बारे में भारत की एक अदालत के उस आदेश को सही ठहराया कि 13 बैंकों के समूह को माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का अधिकार है।

इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक , बैंक आफ बड़ौदा , कारपोरेशन बैंक , फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पंजाब नेशनल बैंक , स्टेट बैंक आफ मैसूर , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। गौरतलब है कि भारत से भागे माल्या पर भारतीय बैंकों को लगभग 9000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वह खुद को भारत प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ एक अलग मामला लड़ रहे हैं। इस मामले में लंदन की एक अदालत में अंतिम सुनवाई अगले महीने होनी है।

नोटबंदी का फायदा अब दिख रहा है: वित्त राज्य मंत्री

मुंबई। केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी का फायदा अब दिख रहा है क्योंकि जो धन घरों में 'यूं ही' रखा था, उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में हो रहा है। बीएसई के एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ''जो धन घरों में निष्क्रिय पड़ा था और उसका कोई उपायोग नहीं था, वह बैंकों में आ गया। इस धन का उपयोग अब देश हित में हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि नोटबंदी के शुरूआती दिनों में लोगों को परेशानी हुई और सरकार को भी आलोचना झेलनी पड़ी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि लेकिन नोटबदी विफल नहीं हुई। शुक्ला ने दावा किया कि 'काला धन' अब 'जन धन' बन गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ''देश का आर्थिक परिदृश्य बेहतर है और निवेशकों के लिये अच्छी धारणा सृजित कर रही है। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भरोसा जताया है। दाल, सब्जी और खाद्य तेल के दाम भी अपेक्षाकृत कम हैं।''

धान की पराली से बायो इथनोल बनाएगी एचपीसीएल

चंडीगढ़। पंजाब के बिजली व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कहा कि धान की पराली से बायोगैस/बायो सीएनजी/बायो इथनोल का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने जारी बयान में कहा कि वर्तमान में प्रदेश में वार्षिक 20 मिलियन टन पराली का उत्पादन होता है। इसका लगभग 20 से 25 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है और बाकी खेतों में जल जाता है। जबकि जो धान की पराली खेतों में जल रही है उससे 5-6 मिलीयन टन बायोगैस/बायो सीएनजी/बायो इथनोल का उत्पादन हो सकता है। कांगड़ ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही सात बायोमास पावर प्लांट चल रहे हैं लेकिन अब धान की पराली से /बायो सीएनजी/बायो इथनोल की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। राज्य ने चार बड़ी कंपनियों से समझौता कर प्लांट लगाने की ओर कार्य शुरु कर दिया है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी वहीं किसानों को इसका लाभ भी होगा। जो धान की पराली किसान के काम की न थी उसकी एवज में किसान को पैसा मिलेगा। वहीं जहां यह प्रोजेक्ट लगेंगे वहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश में देश की बड़ी- बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं और हमने इन कंपनियों से अनुबंध भी कर लिया है। जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, वरबियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिका बायो यूल डेवलेपमेंट लिमिटेड के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। यह कंपनियां धान की पराली से बायोगैस/बायो सीएनजी/बायो इथनोल का उत्पादन करेंगी।

एचपीसीएल धान की पराली से बायो इथनोल बनाएगी जो कि पेट्रोल व डीजल के मिश्रण में काम आता है। कांगड़ ने कहा कि एचपीसीएल यह प्लांट जिला बठिडा के तलवंडी साबो तहसील के गांव नसीबपुरा में लगाएगी। जिसकी लगभग कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और इसको लगाने की दिशा में काम चल रहा है। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1000 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। प्लांट लगने के बाद यहां प्रति दिन करीब 500 टन धान की पराली का प्रयोग होगा और रोजाना इस पराली से 100 किलो लीटर बायो इथनोल बनेगा।

ब्रिटेन ला रहा है टियर टू वीजा में बदलाव, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को मिलेगा लाभ

लंदन (एजेंसी)।

ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव कर इसे संसद के विचारार्थ पेश किया है। इन बदलावों में भारत जैसे देशों के उच्च प्रशिक्षित पेशेवर के लिए कड़े वीजा कोटा नियमों की समीक्षा करना शामिल है। उसकी इस पहल की भारत और ब्रिटेन के उद्योगों ने सराहना की है।

आव्रजन नीति में बदलाव से उन उद्योगों को अपने यहां सेवा देने के लिए भारत जैसे देशों से प्रोफेशनल्स लाने में आसानी होगी और इसके साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी काफी लाभ होगा । ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री केरोलाइन नोक्स ने बताया कि आज के इन बदलावों से हम अपनी फ्रंटलाइन सेवाओं की मांगों को पूरा करने में सक्षम होंगे और अपने उद्योगों के लिए अच्छे पेशेवरों को भी आकर्षित कर सकेंगे।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष रशेश शाह ने कहा कि भारतीय प्रोफ़ेशनल्स की पुरानी मांगों के बीच ब्रिटिश सरकार की ओर से टियर टू वीजा कैटेगरी को आसान बनाने का कदम एक स्वागतयोग्य घटनाक्रम है । यूके सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उच्च कुशल पेशेवरों के आने जाने को सुगम बनाएगा और लंबे समय तक ब्रिटेन के उद्योग की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेगा।

ब्रिटेन में डाक्टरों और नर्सों की कमी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पहले ही यह घोषणा की थी कि यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आने वाले चिकित्सकों एवं नर्सों को टियर टू वीजा से छूट होगी। कन्फेडरेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्री के मुख्य नीति निर्देशक मैथ्यू फेल ने बताया कि उद्योग इन सुधारों का स्वागत करेगा, क्योंकि यह एक अच्छा कदम है।

अंतरराष्ट्रीय कौशल और प्रतिभा ब्रिटेन के वैश्विक नियोक्ताओं का मुख्य आधार है । उन्होंने कहा कि एक सफल आव्रजन प्रणाली को ब्रिटेन के समाज और यहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि संख्या पर। जबतक आव्रजन व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, नौकरी सृजित करने तथा वृद्धि के लिए जरूरी लोगों को अपने यहां बुलाने के लिए उद्योग एवं व्यापार जगत संघर्ष करते रहेंगे।

सूरत। महाराणा प्रताप जन्म जयंती के अवसर पर गोड़ादरा क्षेत्र में भव्य बाईक रैली निकाल महाराणा प्रताप की प्रतिम को पुष्पांजलि अर्पित की गई।

रेलवे स्टेशन पर रिक्शावाला और कुली आमने-सामने

सूरत । रेलवे स्टेशन पर पिछले कई दिनों से ई रिक्शा के कार्यान्वयन का कुलियों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा था। तब आज कॉन्ट्राक्टर द्वारा ई-रिक्शा शुरू किए जाने पर कुलियों ने रोजगार को लेकर विरोध दर्ज कराया था। जिसकी वजह से ई रिक्शावाला और कुलियों के आमने-सामने आ जाने पर पुलिस को बुलाना अनिवार्य हो गया था। सूरत रेलवे स्टेशन पर २६० कुली यात्रियों के सामान ढोने के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। अब सामान के लिए रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा रखी गई है। जिसका किराया कुलियों से कम है। जिसकी वजह से रोजगार को लेकर कुलियों द्वारा ई रिक्शा का कई दिनों से विरोध कर रहे है फिर भी कॉन्ट्राक्टर द्वारा शनिवार को रिक्शा शुरू की गई थी। ई रिक्शा शुरू हो इसके साथ साथ ही कुलियों ने विरोध दर्ज कराया गया था और विरोध हाथापाई तक पहुंच गई थी।

सीटीएम के पास विचित्र प्रकार की ट्रिपल दुर्घटना

घायल पत्नी अस्पताल में उपचार के तहत : कपल रोड क्रॉस कर रहा था तब ट्रिपल दुर्घटना की चपेट आया

अहमदाबाद । शहर में तेजी से वाहन चलानेवाले वाहनचालकों के कारण हर एक-दो दिन में निर्दोष राहगीर की दुर्घटना में मौत हो रही है। शनिवार को सुबह में सीटीएम सर्कल के पास रोड क्रॉस कर रहा कपल विचित्र प्रकार के पैदा हुए ट्रिपल दुर्घटना में शिकार हो गया, जिसमें पति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि पत्नी को इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आयी थी। घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में भारी सनसनी मच गई थी, सीटीएम सर्कल के पास कुछ समय के लिए ट्राफिक चक्काजाम के दृश्य खड़े हो गए। पुलिस ने पूरी घटना के मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। विचित्र प्रकार के इस दुर्घटना में ट्रक और लक्जरी के बीच कपल आ जाने पर पति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल पत्नी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करायी गई थी। दूसरी तरफ नारोल क्षेत्र में भी एक बुजुर्ग महिला को बाइकचालक ने चपेट में लेने पर इसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जबकि रखियाल में भी एक युवक पर ट्रक का टायर चढ़ जाने से इसकी मौत हो गई थी। शहर में दुर्घटना की घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को और एक दुर्घटना हुई है। शहर के सीटीएम एक्सप्रेस हाइवे पर ट्रिपल दुर्घटना हुई है । यह ट्रिपल दुर्घटना के दौरान रास्ता पार कर रहे एक कपल चपेट में आने पर पति की मौत हुई है।

जबकि पत्नी को गंभीर चोटें आने पर उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करायी गई थी । इस बारे में यह जानकारी है कि, नरोडा का कपल घर जाने के लिए शटल रिक्शा पकड़ने के लिए रास्ता पार कर रहा था, इस दौरान ट्रक, बस और अन्य एक वाहन के बीच दुर्घटना हुई थी। इस दौरान ट्रक ने कपल को चपेट में लेने पर राहुल मेघाणी (उम्र.२७) की मौत हुई थी। जबकि उनकी पत्नी सुमन मेघाणी को गंभीर चोटें आयी जिसकी वजह से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करायी गई थी।

रमजान महीना पूरा हो गया है। रमजान महीने के अंतिम दिन में ईद को मनाया गया और एक-दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं दी गई थी।

महिला मरीजों के साथ कामलीला का आनंद लेता

बडौदा के अनगढ का डॉ. प्रतीक आखिर में गिरफ्तारी

कम्पाउन्डर ने दुष्कर्म के १३५ वीडियो बनाये : डॉक्टर क्लीनिक से नशीला इन्जेक्शन-गर्भनिरोधक दवाईयां मिली

अहमदाबाद । बडौदा के अनगढ गांव में सैक्स मेनियाक डॉक्टर प्रतीक जोषी द्वारा कई महिलाओं के साथ उपचार के बहाने दुष्कर्म करने के केस में पिछले कई दिनों से फरार चल रहे लंपट डॉक्टर प्रतीक जोषी को पुलिस ने आखिर में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार होने पर गांव के लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में डॉक्टर ने महिला मरीजों के साथ अपनी कामलीला के काम को कबूल कर लिया था लेकिन इसके साथ में इसके कम्पाउन्डर दिलीप गोहिल और गांव के उपसरपंच द्वारा इसे अक्सर ब्लेकमेइल करके इसका बड़ा सौदाबाजी करते होने का चौंकानेवाला खुलासा भी किया था। जिसकी वजह से पुलिस ने अब यह पूरे मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर द्वारा इसे फंसाया गया है यह बचाव भी पुलिस के समक्ष पेश किया गया था लेकिन पुलिस अब इसकी पूछताछ के आधार पर समग्र प्रकरण में मूल तक पहुंचना चाहती है । कुछ दिन पहले ही नंदेसरी पुलिस ने आरोपी कम्पाउन्डर दिलीप गोहिल की गिरफ्तारी करने के बाद की गई पूछताछ में चौंकानेवाला खुलासा सामने आया था। जिसमें आरोपी कम्पाउन्डर ने सैक्स मेनियाक डॉक्टर के १३५ वीडियो बनाये गये थे, जिसमें कई उसने डिलिट भी कर दिए थे और कई वीडियो उसने अपने मित्र सर्कल में भी भेजा था । पुलिस ने इसके अलावा एक पेन ड्राइव में से भी २५ अन्य वीडियो जब्त किए गए थे। पुलिस की जांच में दुष्कर्म बाद वीडियो बनाने के केस में गांव के ही कई लोग कामलीला का वीडियो बताकर डॉक्टर प्रतीक जोषी को ब्लेकमेइल करते होने का भी सामने आया था । जिसमें अनगढ गांव के उप सरपंच की भी इसमें भूमिका होने का भी सामने आया था। पुलिस की जांच के दौरान डॉ. प्रतीक जोषी के क्लीनिक में से नशीला इंजेक्शन और गर्भनिरोधक दवाईयां मिली।

मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज पढ़कर दुआ मांगी

गुजरातभर में ईदमिलाद को उत्साहपूर्वक मनाया

शहर की ८० से ज्यादा मस्जिदों में अल्लाह की इबादत के अनूठा दृश्य सामने आये मुस्लिम समाज में उत्साह

अहमदाबाद । गत दिन चांद दिखाई देने पर चांद कमिटी द्वारा शनिवार को ईद की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसकी वजह से शनिवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान ईद को भव्य तरीके से मनाया गया। शहर की ८० से ज्यादा मस्जिदों में शनिवार को मुस्लिम द्वारा ईद-उल-फित्र के अवसर पर ईद की विशेष नमाज पढ़कर दुआ मांगी गई थी। ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक-दूसरे से मिलकर ईदमुबारक कहकर त्यौहार की शुभकामनाएं दी है । मस्जिदों में ईद के त्यौहार को लेकर समाज में शांति, सदभाव और परस्पर भाईचारा की भावना ज्यादा मजबूत हो और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना की गई थी। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी सहित के महानुभाव ने भी राज्य के मुस्लिम समाज को ईद-उल-फित्र की शुभकामनाएं दी थी। रमजान महीना पूरा होने के बाद ईद को मनाया जाता है । गत दिन चांद दिखाई देने के बाद शनिवार को ईद का उत्सव मनाने को लेकर आधिकारिक घोषणा की गई थी । जिसके संदर्भ में मुस्लिम समुदाय में गत दिन रात से ही भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था और बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी । शनिवार को सुबह से मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय भाई-बहनों और बच्चे तैयार होकर एक-दूसरे को ईद के त्यौहार की शुभकामनाएं दी है। शीर खुर में खिलाकर एक-दूसरे को संबंधों की मीठाश जीवन में बरकरार रखने की अनूठा तरीका निभाया गया था। दूसरी तरफ, शहर की ८० से ज्यादा मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई थी । शहर की जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज काफी बड़ी संख्या में एकत्र हुआ था और ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई है । ईद-उल-फित्र के अवसर पर शुक्रवार को देशभर के मुख्यबाजारों में रोनक और खरीदी करनेवालों की चहलपहल देखने को मिली थी।

ट्रेलर दीवार तोड़कर दुकान में घुसा : गार्ड की मौत

दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि ट्रेलर ने आसपास की तीन दुकानों को नुकसान करके ३० से ४० अंदर घुस गया

अहमदाबाद। शहर के गोता ब्रिज के निकट शनिवार को सुबह में कपची से भरा ट्रेलर चालक ने अंधाधुंध गति से चलाकर कार वोशिंग के एक गेरेज में ट्रेलर घुस गई जिसकी वजह से बाहर सोये हुए सिक्योरिटी गार्ड की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि ट्रेलर ने आसपास की तीन दुकानों को नुकसान करके ३० से ४० अंदर घुस गई। दुर्घटना के बाद ट्रेलरचालक फरार हो गया था। ए डीविजन ट्राफिक पुलिस ने पूरी घटना के मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है । इस बारे में यह जानकारी है कि, एसजी हाईवे पर गोता ब्रिज के निकट पेट्रोल पंप के सामने स्टार इकोग्रीन एनर्जी सोल्युशन नाम का कार वोशिंग का गेरेज स्थित है। गेरेज के पास में स्टार केफे और न्यू एगवर्ल्ड नाम की फास्टफूड की दुकान स्थित है। गेरेज में ओमप्रकाश बब्बनभाई पांडे (उम्र.४८, निवासी-गोता हाउसींग बोर्ड, गोता) सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर डयुटी करते है। गत दिन रात को वह गेरेज के बाहर पलंग में सो रहे थे। इस दौरान भरा एक ट्रेलर अंधाधुंध गति से गेरेज की तरफ आया था और बाहर सोये हुए ओमप्रकाश को टक्कर मारकर दरवाजा तोड़कर पास में स्थित एगवर्ल्ड की दुकान में घुस गई थी। दुर्घटना के बाद ट्रेलरचालक फरार हो गया था। ए डीविजन ट्राफिक पुलिस ने पूरी घटना के मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है । इस बारे में यह जानकारी है कि, एसजी हाईवे पर गोता ब्रिज के निकट पेट्रोल पंप के सामने स्टार इकोग्रीन एनर्जी सोल्युशन नाम का कार वोशिंग का गेरेज स्थित है। गेरेज के पास में स्टार केफे और न्यू एगवर्ल्ड नाम की फास्टफूड की दुकान स्थित है। गेरेज में ओमप्रकाश बब्बनभाई पांडे (उम्र.४८, निवासी-गोता हाउसींग बोर्ड, गोता) सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर डयुटी करते है। इस दुर्घटना में ओमप्रकाश को शरीर के हिस्से में काफी गंभीर चोटें आयी जिसकी वजह से उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि ट्रेलर दो दुकान तोड़कर सामने आयी दीवार से टकरा गई थी । ट्रेलर का आगे का हिस्सा भी दब गया था। दुर्घटना के बाद ट्रेलरचालक फरार हो गया था।

दो भाई आंगडियापीढ़ी का ५० लाख लेकर फरार

रिलीफरोड की ब्रांच में मैनेजर और आसिस्टन्ट मैनेजर के तौर पर नौकरी करते दो भाई ने पीढ़ी में हाथ साफ

अहमदाबाद। राजकोट की आंगडियापीढ़ी की अहमदाबाद के रिलीफरोड पर स्थित ब्रांच में मैनेजर और आसिस्टन्ट मैनेजर के तौर पर नौकरी करते दो भाई पीढ़ी के ५० लाख रुपये लेकर फरार हो जाने की घटना की वजह से आंगडिया सर्कल में भारी सनसनी मच गई है । आंगडियापीढ़ी के मालिक ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में इस मामले में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने अपराध दर्ज करके दोनों आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, राजकोट एयरपोर्ट रोड पर पृथ्वी आराधना सोसाइटी में रहते पार्थ पृथ्वीसिंह डोडिया (उम्र.३५) राजकोट दीवानपरा क्षेत्र में जय सोमनाथ एंड कंपनी के नाम पर आंगडियापीढ़ी है । अहमदाबाद के रिलीफरोड पर झवेरीवाड में उनकी ब्रांच स्थित है। पाटण के चाणस्मा तहसील के कंबोई गांव में रहते नवलभाई वेलजीभाई ठाकोर और जगदीश वेलजीभाई ठाकोर रिलीफरोड पर इस ब्रांच में मैनेजर और आसिस्टन्ट मैनेजर के तौर पर डयुटी करते थे। गत १८ मई, २०१८ के दोपहर तक दोनों में से एक का भी पार्थभाई पर हिसाब के लेनदेन मामले में फोन नहीं आने पर उनके मोबाइल पर फोन किया था। मोबाइल स्वीच ऑफ आने पर पीढ़ी में काम करते वसंतभाई शाह को फोन करके पूछने पर दोनों भाई आंगडियापीढ़ी में से रुपया लेकर किसी को देने के लिए निकले होने का बताया था। आशंका होने पर पार्थभाई अहमदाबाद आये थे। पीढ़ी में जांच करने पर ५० लाख रुपये लापता था। दोनों भाई रुपये ले गये होने से उनका भाई विष्णुभाई वेरसीभाई ठाकोर को फोन करके पूछने पर मुझे नवलभाई और जगदीशभाई के मामले में फोन नहीं करो, आपका पैसा नहीं मिलेगा, फिर से फोन किया तो जान से मार दूंगा ऐसी धमकी दी थी।

एसएमएस के जरिए शिकायत संख्या तुरंत उपलब्ध

रेलयात्रियों की मदद में रेल मदद मोबाइल एप बनाया

अहमदाबाद। अब रेलयात्रियों की मदद में रेल मदद मोबाइल एप आया है, जो रेलयात्रियों की शिकायतों ो निपटाने की प्रक्रिया में न सिर्फ सुधार लाएगा बल्कि तेज भी बनाएगा। रेल प्रशासन ने पहली बार यह शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पुरी तरह से डिजिटल बनाया है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने हाल में रेल मदद एप लांच किया। रेल मदद जो कि यात्रा के दौरान वांछित सहायता के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे उत्तर रेलवे ने विकसित किया है। यह एप यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करेगा और उनकी शिकायतों को निपटाने की स्थिति के बारे में लगातार जानकारी मुहैया कराएगा। यात्री को पंजीकरण के बाद एसएमएस के जरिए शिकायत संख्या तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद रेलवे की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। इसके पीछे की बैक-एंड-प्रणाली विभिन्न स्त्रोंतो से प्राप्त शिकायतों को एक जगह संग्रहित करेगी, उनका विश्लेषण करेगी और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैनात करेगी ताकि उच्च प्रबंधन प्रत्येक विभाग, डिविजन और फील्ड यूनिट के प्रदर्शन की विभिन्न स्तरों पर निगरानी कर सके।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com